शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 मार्च 2014

आधुनिक दलितों के विकास में गरीबी एक बाधक तत्व
उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में

नानकचंद, केशलता (शोधार्थी)
मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकाय
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा, उत्तरप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

भारतीय समाज में दलितों की गरीबी के प्रादुर्भाव में जाति व्यवस्था विशेष कारक रहा है, जिसका प्रतिबिम्ब आज के प्रौद्योगिक युग में दिखाई पड़ता है। अशिक्षा का अभाव के कारण दलित अपने उद्देश्यों को साकार करने में पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो रहे हैं। दलितों की सामाजिक और आर्थिक समस्या का निराकरण करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की हैं। इस शोध पत्र के द्वारा यह प्रकाश डालने का प्रयास किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के दलितों के सामाजिक-आर्थिक विकास के मार्ग में वे कौन-सी चुनौतियाँ हैं जिसके कारण दलित पूर्ण रूप से सशक्त नहीं हो पाये हैं ? उत्तर प्रदेश के दलितों के उत्थान में मनरेगा कहाँ तक मददगार साबित हुई हैं ?

प्रस्तावना

भारत के लोग परिश्रमी और सृजनात्मक होते हैं। इस देश का लोकतंत्र वास्तव में शानदार है जिसकी जड़ें बेहद मजबूत हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि आज़ादी के 67 वर्षों के पश्चात भी भारत गरीब देश क्यों है ? गरीबी एक ऐसी समस्या है, जिसका सामना समूची दुनिया कर रही है, जहां तक विकासशील देशों का सवाल है, उनमें से भारत इस बीमारी का ज्यादा शिकार हैं। दुनिया में भूखे लोगों वाले 79 देशों की सूची में भारत 75वें नंबर पर है. संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक 2012 में भारत में 21.7 करोड़ लोग कुपोषित थे, सिर्फ इतना ही नहीं पांच साल से कम उम्र के करीब आधे बच्चे कुपोषित हैं।1 हमारे यहां गरीबों की गणना पर विवाद होता रहा है उसकी मिसाल कहीं दूसरे देशों में नहीं मिलती। यहां गरीब आंकड़ेबाजी में उलझकर रह गया है, कहने का तात्पर्य यह है कि गरीबी का सही आंकड़ा आज तक सामने नहीं आ सका है। आज तक न तो योजना आयोग और न ग्रामीण विकास मंत्रालय ही इसका सही-सही आंकड़ा पेश कर सका है, जबकि गरीब और गरीबी का पूरा हिसाब-किताब, लेखा-जोखा ये दोनों रखते हैं। सच तो यह है कि गरीबों के कष्ट, उनके दुख-दर्द तो तभी दूर हो पाएंगे जब एक तो उनकी निश्चित जनगणना ईमानदारी से प्रस्तुत की जाए और दूसरा उनके बारे में सकारात्मक सोच हो।

लेकिन भारत में गरीबों की जनगणना के बारे में ही विवाद है तो गरीबी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान कैसे हो पाएगा। सरकार को यथार्थ का आकलन कर अशिक्षा, बेरोजगारी के कारण पर्याप्त भोजन-पोषण की अनुपलब्धता, गरीबी, महंगाई और असमानता के कारणों पर ध्यान देते हुए गरीबों के प्रति समाज के उत्तरदायित्व के बारे में सोचना होगा। निजी क्षेत्र के विस्तार के बावजूद उसमें रोजगार की कांट्रेक्ट प्रणाली, अस्थायीकरण, मनमानी छंटनी और श्रम कानूनों का बढ़ता उल्लंघन किस दिशा की ओर संकेत करता है ? हमारी आबादी का 60 फीसद हिस्सा कृषि पर निर्भर है लेकिन जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी मात्र 14 फीसद ही है। जाहिर है कि गैर बराबरी कहें या दिन-दूनी बढ़ती असमानता के चलते इन हालात में गरीबी का निर्धारण कतई न्यायोचित हो ही नहीं सकता, जबकि सही मायने में देश के दलितों के पिछड़ने का कारण जातिगत भेदभाव और अशिक्षा ही है। जनगणना 2001 के अनुसार, उत्तर प्रदेश में दलितों की जनसंख्या 3 करोड़ 57 लाख है।

गरीबी का अर्थ और परिभाषाएँ

गरीब वह हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ पीने का पानी और साफ-सफाई की खराब उपलब्धता, अपर्याप्त क्षमता, आवास, कपड़ा, भोजन, समान अवसर और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सरकार भले आंकड़ों की बाजीगरी के चलते उनकी संख्या कम दिखाने का प्रयास करे लेकिन उनके लिए कुछ तो ईमानदारी के साथ करना होगा जिससे इस समस्या से निजात पा सकें । योजना आयोग ने गरीबी के निर्धारण पर गठित की गई तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को अपना रखा है। सरकार की ताजा परिभाषा के अनुसार अगर ग्रामीण इलाके का कोई व्यक्ति रोजाना 27 रुपये 20 पैसे से अधिक कमा रहा है, और किसी शहरी की आय 33 रुपये 30 पैसे से अधिक है तो वे गरीब नहीं हैं। इससे पहले 2011 में योजना आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के अनुसार अगर शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति रोजाना 32 रुपये से अधिक या मासिक 965 रुपये से ज्यादा अपने गुजर बसर पर खर्च कर रहा है तो वह गरीब नहीं है। इसी तरह अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति अपने जीवनयापन के लिए 26 रुपये से अधिक प्रतिदिन या 781 रुपये मासिक से अधिक खर्च कर रहा है तो वह गरीब नहीं है।2 पहले निर्धारित कैलोरी वाली खुराक खरीदने की सामर्थ्य वाली मौद्रिक सीमा से गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता था। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 2400 किलो कैलोरी वाली खुराक और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 किलो कैलोरी वाली खुराक नियत की गई थी। ज्यादा शारीरिक परिश्रम करने के चलते गांवों के लोगों के लिए अधिक कैलोरी का मानक बनाया गया।3 ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्युमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव द्वारा एक अध्ययन में गरीबों की संख्या करीब 65 करोड़ बताई गई। इस अध्ययन में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का उपयोग किया गया था। इसके अनुसार 42.1 करोड़ गरीब केवल आठ उत्तरी भारतीय राज्यों में रहते हैं। गरीबों की यह संख्या 26 सबसे गरीब अफ्रीकी देशों की आबादी 41 करोड़ से भी अधिक है।4

एक अमेरिकी कंपनी का सर्वे यह खुलासा करता है कि भारत में गरीबों की हालत क्या है तो उसके अनुसार देश में 1.25 फीसद आबादी के अलावा हर आदमी किसी न किसी पैमाने पर गरीब है। कोई

बीमार है, कोई असहाय बूढ़ा है जो अपना इलाज कराने में असमर्थ है.इसी तरह किसी के पास रहने को अच्छा क्या, घर भी नहीं है और किसी के पास पीने के पानी की उचित व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे करोड़ों लोग गरीब ही हैं, उन्हें अमीर नहीं कहा जा सकता। यह बात उल्लेखनीय है कि उनमें से 48 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में गरीब हैं।5

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के आंकड़े गवाह हैं कि भारत के पिछड़े-गरीब सात राज्यों में 16 जिलों के तकरीब 75 फीसद परिवारों को दो जून की रोटी भी मयस्सर नहीं है, 29 फीसद बमुश्किल अपना पेट भर पाते हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार उच्च वर्ग को भोजन के माध्यम से हासिल कैलोरी से 30 से 50 फीसद से भी कम देश की ज्यादातर आबादी को मिल पाता है। भारतीय योजना आयोग ने जो आंकड़े दिए हैं उनके मुताबिक वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2011-12 के दौरान 13.8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत की 1.2 अरब की आबादी में अब 26.9 करोड़ लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया का कहना है, "सबसे पहले तो विकास ने नौकरी के बेहतर मौके और बढ़िया वेतन पैदा किया है और इस तरह से गरीबों को फायदेमंद रोजगार मिला है."

कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पनगढ़िया और मोरे के अनुसार गरीबी भारत के दलित-आदिवासी समुदायों में अगड़ी जातियों के मुकाबले, और मुसलमानों में हिंदुओं के मुकाबले अधिक तेजी से कम हुई है। 2004-05 और 2011-12 बीच के सात सालों का विश्लेषण किया गया है। इस दौरान भारत में गरीबी 15.7 प्रतिशत नीचे आई। दलितों में गरीबी का अनुपात 21.5 प्रतिशत गिरा जबकि आदिवासियों में यह गिरावट 17 प्रतिशत के करीब थी। इनके मुकाबले अगड़ी जातियों में गरीबी की गिरावट काफी कम (10.5 प्रतिशत) थी। दक्षिणी और पश्चिमी भारत में भी दलितों में गरीबी कम हो रही है। केरल और तमिलनाडु के दलित सबसे कम गरीब हैं। 2011-12 में 29.4 प्रतिशत दलित और 43 प्रतिशत आदिवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे थे।6

उत्तर प्रदेश में दलितों के पिछड़ने के कारण

जनगणना 2001 के अनुसार, उत्तर प्रदेश में दलितों की जनसंख्या 3 करोड़ 57 लाख है। उत्तर प्रदेश में 78 जिले हैं । यह कहना अतिशियोक्ति नही होगा कि यह राज्य अनेक संतो, ऋषि मुनियों, समाज सुधारकों और राजनीतिज्ञो का स्थल रहा है, लेकिन गरीबी की समस्या से यह राज्य भी अछूता नहीं रहा है।

सामाजिक कारण- जाति व्यवस्था, दहेज प्रथा, सामाजिक कुरीतियाँ, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, सुस्तपन, दुर्घटना, नीति और मूल्यों का अभाव आदि

भोगोलिक कारण- प्राकृतिक संसाधनों का अभाव, चक्रवात, बाढ़ आदि

राजनैतिक कारण- भ्रष्टाचार, युद्ध, क्रमबद्ध योजनाओ का लागू न होना आदि

आर्थिक कारण- भूमिहिन होना, मजदूरों का शोषण प्रतिस्पर्द्धा आदि

हजारों वर्षो से दबे-कुचले दलित अब बिजनेस की दुनिया में भी जगह बना रहे हैं। संपर्को, संसाधनों के

मोर्चे पर पिछड़े दलितों को कारोबार की मजबूत किलेबंदी भेदने में दिक्कतें तो आ रही हैं, लेकिन उन्हें सफलता भी मिल रही है। फिक्की, एसोचैम और सीआइआइ की तर्ज पर दलितों ने भी अपना संगठन दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) बना लिया है। उद्यमिता की ओर दलितों के झुकाव की प्रमुख वजह सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगारों के अवसरों में कमी आना है। 1997 में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार 197 लाख थे। इसके बाद इनमें लगातार गिरावट आ रही है। 2007 में यह आंकड़ा 180 लाख पर आ गया। इसके अलावा 20 करोड़ की दलित आबादी के लिए पहले भी पर्याप्त सरकारी रोजगार उपलब्ध नहीं थे। अब दलितों का समय है। दलित व्यापार में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रभान प्रसाद का कहना है- हम भी बाबा साहब अंबेडकर की तरह सूट पहनते हैं। अंग्रेजी बोलते हैं। हम आरक्षण के बल पर नहीं, अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। कभी दलितों के हाथ का छुआ न खाने वाले आज कारोबार में उनकी भागीदारी का स्वागत कर रहे हैं। नैनो, पल्सर, हीरो होंडा बनाने में दलितों की भागीदारी है। भारत में करीब 20 करोड़ दलित हैं।

दलित चिंतक डी श्याम बाबू के मुताबिक देश की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी छठे भाग के बराबर है, पर उनके पास देश की संपत्ति का सिर्फ एक फीसद हिस्सा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम जैसी सरकारी संस्थाओं के गठन के बावजूद दलित कारोबारी समुदाय को पूंजी हासिल करने में हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर अब दलित सरकारी नौकरियों पर ही निर्भर नहीं रहे। वे कारोबार की दुनिया में दस्तक दे रहे हैं। वे नए सपने देख रहे हैं और उन्हें साकार करने में जुटे हैं।

उत्तर प्रदेश के दलितों के उत्थान में मनरेगा का योगदान आज़ादी के 67 वर्षों के बाद भी उत्तर प्रदेश के दलित पूर्ण रूप से सक्षम नज़र नहीं आ रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएँ समय समय पर क्रियान्वित की गयी हैं - आई.आर. डी.पी., एस.जी.एस.वाई., आई.ए.वाई और मानरेगा आदि। ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदाय का विकास आर्थिक योजनाओं का प्रमुख विषय रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालाय भारत के दलितों की गरीबी, भूख को मिटाने के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित नरेगा सरकार का एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबों को रोजगार दिलाना है। नरेगा योजना को 2 फरवरी, 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू किया गया और उसके पश्चात 2007-08 में 130 शामिल किए गए और 2008-09 से देश के विशेष जिलों में लागू किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 2006-07 में कुल निधि 7980.73 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए जिसमें से अनुसूचित जाति को 15.58 करोड़ और अनुसूचित जन जाति को 23.46 करोड़ रोजगार दिलाया गया। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के लिए 33242.07 करोड़ रूपये निर्धारित किए

- तालिका-1 कुछ राज्यों की तुलनात्मक आय

State	8th FYP (1992-97)	9th FYP (1997-02)	10thFYP (2002-07)	11th FYP (2007-12)
Bihar	3.9	3.7	6.9	9.9
M.P.	6.6	4.5	5.0	9.2
U.P.	5.0	2.5	5.8	7.1
Average	5.16	4.22	6.38	8.8

तालिका 2 रोजगार, मनरेगा के अंतर्गत 2011-12 & 2012-13 (प्रति व्यक्ति)

Year	2011-2012	2012-2013
SC	866.87	302.87
% of SC participation	32.53	33.66
ST	33.24	9.99
% of ST participation	1.25	1.11
No. of household availed 100 days of employment	306398	15087
% of household completed 100 days employment	4.19	0.34

Sources: annual report, 2011-13

सुझाव

दलित विचारक व चिंतक चंद्रभान प्रसाद ने कहा है कि देश के दलितों के उत्थान की प्रक्रिया में आरक्षण के मुकाबले मुक्त बाजार व्यवस्था ज्यादा कारगर है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण की व्यवस्था महज 10 प्रतिशत लोगों का फायदा कर सकती है जबकि मुक्त बाजार व्यवस्था में 90 प्रतिशत दलितों के उत्थान की क्षमता है। यह कहना सत्य प्रतीत होता हैं कि बाजार की विशेषता जात-पात से ऊपर उठकर अधिकतम लाभ प्राप्त करने की होती है। यह बाजारवाद के बढ़ते प्रभाव का असर ही है कि आज सवर्ण जाति के लोग भी बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स, पांच सितारा होटलों आदि में हाऊस कीपिंग व सिक्योरिटी गार्ड का काम करते दिखाई पड़ते हैं जो पूर्व में सिर्फ दलितों का काम माना जाता था और मुक्त बाजार व उदारवाद के कारण मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में आज जातियों के बीच खानपान, रहन सहन व पहनावे का भेद मिट चुका है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के दलितों को बिजनेस में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। भारत की जीडीपी की वार्षिक विकास दर छह फीसदी है। इस गति से तो हमें आज के मैक्सिको के करीब पहुंचने में पचास साल और लग जाएंगे। आखिर हम 10 फीसदी की वार्षिक विकास दर क्यों हासिल नहीं कर सकते ? उस दर से भी हम आज के अमेरिका तक पचास साल में पहुंचेंगे।

निष्कर्ष

उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि उत्तर प्रदेश विश्व बाजार में भी नाकामयाब है जहां आसियान और पूर्व एशिया के ही उद्यमियों की तूती बोलती है। सरकारी नीतियों के कारण भारतीयों की प्रगति में बाधा का यह एक सटीक उदाहरण है। उद्यमी बुनियादी तौर पर मेहनती और किसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए समर्पित लोग होते हैं। उद्यमियों के बीच प्रतिस्पर्धा ही अर्थव्यवस्था को गति देती है। ऐसे में जहां वे खुद तरक्की करते हैं

वहीं समाज के लिए रोजगार निर्माण करके उसे आर्थिक संबल देते हैं। अर्थव्यवस्था की ट्रेन को खींचने में उनकी भूमिका इंजिन की तरह होती है। कहने का तात्पर्य यह हैं कि उद्दमिता का विकास किया जाए। अमेरिका उस राजनीति का अनुसरण करता है जिससे संपत्ति का सृजन होता है जबकि भारत उस राजनीति का अनुसरण करता है जिसमें संपत्ति का पुनर्वितरण होता है.राष्ट्रीय संपदा के अभाव में भारत गरीबी का पुनर्वितरण करता है और गरीब ही बना रहता है जबकि अमेरिका ज्यादा अमीरी से और भी ज्यादा अमीरी की ओर बढ़ता है।

संदर्भ सूची

1 आंकड़ों में उलझी भारत की गरीबी, दुनिया न्यूज पेपर 7 अगस्त 2013

2 गरीब कौन हैं दैनिक जागरण, 29 जुलाई 2013

3 Ibid

4 Ibid

5 ज्ञानेन्द्र रावत, ऐसे तो खतम नही होगी गरीबी, राष्ट्रिय सहारा न्यूज पेपर, 17 ओक्तुबर 2013

6 स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर, दलितों और मुसलमानों के घर तक पहुंची ग्रोथ नवभारत टाइम्स ओक्तुबर 17 2013